International Journal of Scientific Research in Science and Technology
© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 11 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X

शैक्षिक परिवेश के उपभोक्ता

डॉ. बीरेन्द्र कुमार
एम.फिल. (जे.एन.यू., नई दिल्ली),
पी–एच.डी. शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, टी.एम.बी.यू., भागलपुर
उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, राजनीति विज्ञान
आर. एन. एंड पी.आर. इंटर उच्च विद्यालय, जलालाबाद, असरगंज, जिला– मुंगेर

संक्षेपिका

शीतयुद्ध की समाप्ति के उपरान्त पूंजीवादी विचारधारा की अगुवाई में बनी एक ध्रुवीय वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में LPG यानी उदारीकरण, नीजिकरण और वैश्वीकरण की लहर से कोई भी देश नहीं बच सका। ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे तीसरी दुनिया सहित अन्य समस्त विकासशील देशों की समस्त आन्तरिक एवं आधारभूत कार्यनीतियों पर इसका तत्काल प्रभाव पड़ना लाजिमी था। इस प्रभाव में खुली एवं उदारवादी विचारधारा वाले देशों को विकसित एवं औद्योगिक देशों ने अपनी औद्योगिक संस्थाओं एवं उसके उत्पादों की मदद से अपनी विकास एवं राष्ट्रीय हितों की अधिकतम सुनिश्चितता के लिए अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों को अपने लिए एक बाजार के रूप में स्थापित किया। अतः इन विकसित एवं पूंजीवादी राष्ट्रों ने कदाचित अपनी नव उपनिवेशवादी अवधारणाओं की परिधि में पिछड़े, अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों की शिक्षा व्यवस्था को समाहित करने का अघोषित कार्यनीतियां बनाई जिसके प्रभाव में न केवल इन राष्ट्रों की शैक्षिक परिवेश में न केवल बाजारवाद का प्रवेश हुआ अपितु यहां के शैक्षिक संस्थान स्वयं एक औद्योगिक एवं पूंजीवादी संस्थान बन गए। परिणामतः इन संस्थानों के इर्द–गिर्द जो भी व्यक्ति कुछ भी लाभ अथवा अवसर की संभावनाओं की दृष्टिकोण से आए वे सभी किसी न किसी रूप में एक उपभोक्ता बन गए जिसका उपभोग उन्हें किसी प्रकार का सहारा अथवा प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति, समूह, नियामक इकाई अथवा शासन–प्रशासन के प्रभावशाली पद या व्यक्ति कर रहे हैं।

मुख्य कुंजी – शिक्षा, व्यवसाय, नैतिकता, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक गतिविधि।

समसामयिक परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण विश्व समुदाय वैश्वीकरण एवं सूचना–प्रौद्योगिकी के प्रभाव में है जिसका एक महत्त्वपूर्ण धूरी भारत है। भारत में वैश्वीकरण के क्रियान्वयन से अद्यतन विश्व समुदाय एकल वैश्विक बाजारीकृत व्यवस्था में तब्दील होता गया जिसका प्रभाव भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पड़ना स्वभाविक था। परिणामतः यहां की शैक्षिक संस्थाएं की कल्याणकारी एवं समाज सरकारी नियंत्रण, कल्याणकारी एवं समाजवादी सीमाओं से मुक्त होने लगी और क्रमशः दो वर्गों– सरकारी और नीजि शिक्षा व्यवस्था में वर्गीकृत होती चली गई। कल्याणकारी एवं समाजवादी मूल्यों के घटते प्रभाव का व्यापक असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ना स्वभावतः था। इसकी समसामयिकता ने शिक्षा को दो वर्गों– सरकारी और नीजि संस्थानों की परिधि में वर्गीकृत कर स्थापित कर दिया जो क्रमशः मात्रात्मक और गुणात्मक शिक्षण के रूप में पहचाना जाने लगा। बढ़ती बेरोजगारी और बदलते शैक्षिक वातावरण में विभिन्न कारणों से अब भारत का शिक्षा के विभिन्न आयाम बदल चुके हैं परिणामतः शिक्षा के इन दो वर्गों के अतिरिक्त दो अन्य वर्ग का उदय हुआ है जिसमें एक है उपादेयता या रोजगारोन्मुखी शिक्षा और दूसरा अधिकतम आय एवं प्रतिष्ठा की शिक्षा। परिणामतः शैक्षिक परिवेश में एक विचित्र प्रतियोगिता का वातावरण तैयार हो चुका है जिसमें अभिभावक, छात्र, शिक्षक, शिक्षण संस्थान और इससे सम्बन्धित नीति–निर्धारक नित नए–नए प्रयोग कर रहे हैं। अभिभावक एवं छात्र बाजारीकृत व्यवस्था में अधिकतम उपादेयता मूलक शिक्षा, जिसमें अल्पकाल में अधिकतम आय एवं प्रतिष्ठा की संभावनाओं के मद्देनजर पारम्परिक शिक्षा के अतिरिक्त मात्रात्मक एवं गुणात्मक शिक्षा का समीकरण बनाते हुए बाजारीकरण के प्रभाव में अपनी वास्तविक आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं नैतिक सीमाओं से विमुख होते जा रहे हैं। इन सभी तथ्यों के तामझाम में वर्तमान में प्रचलित निजी संस्थान संचालक, ट्यूटर एवं शिक्षा के विचौलिए सरकारी नीतियों की आड़ में अभिभावक एवं छात्रों को अपना उपभोक्ता मान उनका यथा संभव आर्थिक शोषण कर रहे हैं।

सम्बन्धित शोध आलेख के संदर्भ में सर्वप्रथम उपभोक्ताओं को चिन्हित करते हुए उसके व्यवहार का अंकन करना आवश्यक है। इस प्रकार के अध्ययन से उपभोक्ता के व्यवहारों के निर्धारकों एवं उसके प्रभावों का सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकार के सन्दर्भ में वर्त्तमान शैक्षिक परिवेश के भविष्य का पूर्वानुमान लगाया जाना संभव हो सकता है। अतः इन सन्दर्भों का बिन्दुवार अध्ययन इस प्रकार है।

उपभोक्ता एवं उनका व्यवहार – शैक्षिक परिवेश में सामान्यतः दो प्रकार के उपभोक्ता हैं– पहला, छात्र एवं उसके अभिभावक जो बेहतर शिक्षा की वकालत करने वाले शिक्षक, धन के बदले शिक्षा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी, संस्थान की कार्यनीतियों का शिकार हैं और दूसरा वे शिक्षक, संस्थान एवं एजेंसियां जो सरकारी नीतियों की आड़ में अपना आर्थिक स्वार्थ सिद्धि करते हैं। यहां अभिभावक एवं छात्रों के रूप में उपभोक्ताओं की मानसिकता, उपादेयता एवं उसके व्यवहारों की व्याख्या अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यही वह वर्ग है जो भारतीय समाज एवं राष्ट्रीयता का भविष्य है। अतः राष्ट्रीय सरोकार में भारतीय शैक्षिक परिवेश के मुख्य उपभोक्ता अर्थात् छात्र यानी युवा वर्ग का अध्ययन–विश्लेषण आवश्यक है।

किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का भविष्य उसके नौनिहालों एवं युवावर्ग पर आश्रित होता है क्योंकि उसका लालन–पालन एवं शिक्षा–दीक्षा जिस प्रकार होती है उसी प्रकार उसके परिणाम भी प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि किसी ने कहा है दुश्मनी का सबसे बड़ा बदला दुश्मन के बच्चों को बर्बाद करना होता है और राजा के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने अनुरूप शिक्षा नीति का निर्धारण करे।

वर्तमान परिस्थिति में ऐसा पाया जा रहा है कि गुणात्मक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा सरकारी संस्थानों में सरकारी पाठ्य पुस्तकों से सरकारी शिक्षकों द्वारा नहीं अपितु निजी संस्थानों में विभिन्न एजेंसियों की पाठ्य पुस्तकों से ट्यूटरों द्वारा दी जा रही है। ऐसी शिक्षा अपेक्षाकृत काफी खर्चीली एवं मंहगी होती है। इसके लिए उनके द्वारा जितना विज्ञापन दिया जा रहा है उससे अधिक अभिभावक एवं छात्र इस बात से विज्ञापित हैं कि सरकारी विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में शिक्षक जिस अमानवीय एवं गैर–शैक्षणिक संवेदनहीनता से अध्यापन करते हैं उससे बच्चों की प्रतिभाओं का स्वभाविक विकास कतई संभव नहीं है। अतः छात्र एवं अभिभावक दोनों अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए फीस आधारित शिक्षक एवं शिक्षण संस्थानों की ओर आकर्षित हैं। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षण संस्थान बच्चों में नैतिक, मानवीय, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा सांस्कृतिक मूल्यों का बीजारोपण या विकास नहीं कर केवल आर्थिक पक्षों के सबलीकरण लिए यथासंभव प्रयास करते हैं। ऐसे छात्र एवं अभिभावक अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि में शीघ्र प्रतिष्ठित होने के लिए केवल शिक्षा के आगम

आर्थिक पक्षों के सशक्तिकरण के लिए अपनी क्षमता एवं दक्षता के अनुपात में अधिकाधिक महत्त्व देते हैं। इस परम्परा में वे छात्र एवं अभिभावक क्रमशः बाजारवाद का शिकार होकर एक उपभोक्ता स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। एक के बाद एक उपभोक्ता की सफलता की नकल से सम्पूर्ण समाज के सम्पन्न व्यक्ति अन्ततः स्वयं एक उपभोक्ता स्वरूप में स्थापित होते जा रहे हैं।

इस प्रकार नीजि आर्थिक एवं रोजगार सम्बन्धी प्रतिष्ठा की कामनाओं को मूर्तरूप देने की दौड़ में ये उपभोक्ता वर्ग अपनी पारिवारिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय महत्त्व को समझ ही नहीं पाते। इसके साथ ही साथ इन उपभोक्ताओं की मानसिकता का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक सशक्तिकरण करने वाले शिक्षक, शिक्षण संस्थान एवं विभिन्न एजेंसियां कानूनी प्रावधानों, नीति–निर्धारकों, राजनेता, प्रशासनिक वर्गों के प्रभाव यथासंभव आर्थिक तरक्की करते हैं।

शैक्षिक परिवेश का निर्धारक – सम्बन्धित संदर्भ में शैक्षिक परिवेश अथवा इसके उपभोक्ता के व्यवहारों का निर्धारक तत्त्व अनेक हैं जो विविधताओं से परिपूर्ण हैं। बढ़ती बेरोजगारी और नौकरी की कड़ी प्रतियोगिताओं के दौड़ में मध्यम एवं पिछड़े आर्थिक पृष्ठभूमि का हरेक अभिभावक एवं अभ्यर्थी अपनी आकांक्षाओं के मद्देनजर यथाशीघ्र रोजगार पाने की चाह में आगे निकलना चाहता है। इस आकांक्षाओं की पूर्ति सरकारी संस्थानों में चल रही कार्यनीतियों से कतई संभव नहीं है। अतः इससे सम्बन्धित ध्येय की पूर्ति हेतु अपेक्षित रोजगार पाने में असफल व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा अधिक आय की कामना में निजी क्षेत्र में चल रहे संस्थान, इस दिशा में नए–नए प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। ऐसी चाहतों एवं प्रयोगों की सफलता के लिए शैक्षिक परिवेश में बाजारवाद विकसित हुआ है। अतः भ्रष्टाचार में संलिप्त अथवा ऐसी संभावनाओं से आच्छादित व्यक्ति, राजनेता, प्रशासनिक पदाधिकारी स्वयं अथवा अपने सहयोगियों के प्रभाव में मानवीय, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय सरोकार के सन्दर्भ में यथोचित योगदान की असमर्थता की स्थिति में पाए जाते हैं। ऐसी जटिल एवं उहापोह की स्थिति में समाज एवं व्यवस्था के सभी पक्ष इसके प्रति उत्तदायी हैं।

प्रभाव – शैक्षणिक व्यवस्था किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का प्रतिबिम्ब होता है। भारत के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों एवं राज्यों का शैक्षिक परिवेश गुणात्मक रूप से एक समान नहीं है। लेकिन समग्रता में यह

कहा जाना अपेक्षित है कि प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक सरकारी संस्थान पूर्णतः खानापूर्ति पर केन्द्रित जहां सम्बन्धित राज्य सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए विद्यालयों एवं शिक्षकों का उपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिहार की बात करें तो विभिन्न योजनाओं के रूप में छात्रों को कम से कम इतनी धनराशि उपलब्ध करा रही है जिससे उस छात्रों की कक्षा के पाठ्यक्रम से अधिक ट्यूशन फी मिल जाती है। यहां शिक्षक और सामान्य प्रशासन दोनों विवश हैं। परिणामतः बच्चों का नैतिक अवमूल्यन हो रहा है। विश्वविद्यालयों की बात करें तो वहां भी आर्थिक उपयोगिता के अतिरिक्त कमोवेश यही स्थिति है। पिछले कुछ वर्षों से आधार कार्ड की अनिवार्यता से विद्यालयों से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्याओं में कमी आई है क्योंकि कई बच्चे सरकारी विद्यालयों में नामांकित होते हुए नीजि विद्यालयों में पढ़ते रहे। ऐसी स्थिति किसी न किसी रूप में समस्त भारत में पाई जाती है। फर्जी और आयातित प्रतिभावान छात्रों की लम्बी सूची इस बात का परिचायक है कि शैक्षिक परिवेश में उपभोक्ता का व्यवहार नैतिक एवं मानवीय दृष्टि से सामाजिक एवं राष्ट्रीय सरोकार के लिए अशुभ है।

सारांश – किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की शैक्षिक स्थिति किसी खास संस्थान, समुदाय या व्यक्ति विशेष की निजी मानसिकता या गतिविधि पर कदापि आश्रित नहीं होती है। इसके लिए उसकी समस्त आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मुद्दे सहित तमाम प्रशासनिक एवं न्यायिक मुद्दे उत्तरदायी होते है। इन तमाम संदर्भों में भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक मुद्दे विशेष रूप से उत्तरदायी हैं जहां संवैधानिक जटिलताओं की आड़ में मानवीय एवं बौद्धिक सम्पदाओं का न तो समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है और न ही उपयोग किसी एक सामान्य नियम–कानून के तहत हो रहा है। अतः भारतीय शैक्षिक परिवेश में उपभोक्ताओं एवं उसके व्यवहारों का सम्पूर्ण अध्ययन–विश्लेषण एक गंभीर शोध का विषय है जिसमें राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और राष्ट्रीय मुद्दे के तत्व प्रभावित होते हैं।

संदर्भ

1. डियरडेन, आर.एफ. (2010) : *शिक्षा विमर्श*, शिक्षा और राजनीति, अंक– जुलाई– अगस्त, जयपुर : दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति, पृ.– 5-13.

2. मीणा, रमेश चंद (2015) : *जनसत्ता*, 'शिक्षा का मायाजाल', नई दिल्ली : द इण्डियन एक्सप्रेस प्रेस, अंक– रविवासरीय, 3 अप्रेल, पृ– 3.
3. यादव, कालिका एवं अल्पना वर्मा (2012) : *संवाद*, 'ऑक्युपेशनल स्ट्रेस अमंग हायर सेकेन्ड्री स्कूल टीचर : अ स्टडी फिल्ड', भोल्युम– 1, नं– 1.
4. सिंह, रावत बीरेन्द्र (2016) : *शिक्षा विमर्श*, 'शोषण को वैधानिकता', जनवरी– फरवरी, अंक– 01, जयपुर रू दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति, पृ.– 40-43.
5. संवाददाता (2013) : *जनसत्ता*, 'बिहार में शिक्षा, उर्जा व आतिथ्य क्षेत्र में निवेश को इच्छुक फ्रांस', 06 दिसम्बर, नई दिल्ली : द इण्डियन एक्सप्रेस प्रेस, पृ– 10.
6. संवाददाता (2013) : *प्रभात खबर*, 'सिनॉपसिस लिखनेवालों की चांदी', भागलपुर संस्करण : 30 मई, पृ– 4.